प्रादेशिक समाचार एकांश, इन्दौर
गुरूवार, दिनांक 17.05.2012, प्रातः 7.05

<u>मुख्य समाचार</u>

- राज्य के सभी 52 हजार गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये सरकार कृतसंकल्पित, कहा मुख्यमंत्री ने।
- देश की सबसे बड़ी सौर उर्जा परियोजना प्रदेश के नीमच जिले में स्थापित होगी।
- इस वर्ष तैयार किये जाएंगे प्रदेश के 12 शहरों के मास्टर प्लान।
- किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पूरी तरह विफल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात का आरोप।

<><><><>

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि राज्य के सभी 52 हजार गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये उनकी सरकार कृतसंकल्पित है। कल भोपाल में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम आदमी को देने के लिये ये योजना आरंभ की गई है, इसके तहत हर 10 गांवों के बीच एक हेल्थ सेक्टर बनाया जाएगा। जहां बिमारियों पर रोक लगाने के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य अमले के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे आम आदमी को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी योजना को गंभीरता से लागू करें। श्री चौहान ने सरकारी डॉक्टरों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उनके वेतनमान बदला जाएगा और उन्हें सम्मानजनक वेतन भत्ते दिये जाएंगे।

<><><><>

देश की सबसे बड़ी सौर उर्जा परियोजना प्रदेश के नीमच जिले में स्थापित होगी। इसके लिये राज्य सरकार ने एक निजी कम्पनी को 125 मेगावॉट उर्जा उत्पादन का ठेका दिया है। पारम्परिक उर्जा स्रोतों की कमी और इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और थर्मल विद्युत परियोजनाओं की बढ़ती लागत के मद्देनजर सौर उर्जा चलित इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बारे में और ब्यौरा हमारे इन्दौर संवाद्दाता सुनील तिवारी से

मध्यप्रदेश में बनने वाले देश के अब तक के सबसे बड़े सोलर पावर परियोजना का ठेका वेलस्पन सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल किया है। प्रदेश के मंदसौर व नीमच जिले में स्थापित होने वाले इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की नीलामी की। इसमें से वेलस्पन को 125 मेगावाट का ठेका हासिल हुआ है। कंपनी ने इसके लिए 8 दशमलव 05 रूपए प्रति यूनिट की दर से बोली लगाई थी। उल्लेखनीय है कि अभी तक किसी भी कम्पनी को मिला ये सबसे बड़ा सोलर पावर परियोजना है। आमतौर पर एक सोलर पावर

परियोजना को स्थापित करने पर 9–10 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट का खर्च आता है। सौर उर्जा जल्द ही गेम चेंजर की भूमिका में आने वाली है और वर्ष 2015 तक इसके टैरिफ थर्मल परियोजना से मिलने वाली पावर के बराबर हो जाएंगे। कंपनी मौजूदा समय में गुजरात, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में 30 मेगावाट की परियोजनाओं का संचालन कर रही है। इसने हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के तहत 50 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट हासिल किए हैं।

<><><><>

राज्यसभा ने कल 2012 के विनियोग और वित्तीय विधेयक को मंजूरी दे दी है। लोकसभा इन विधेयकों को पिछले सप्ताह ही मंजूर कर चुकी है। राज्यसभा में बहस का उत्तर देते हुए केन्द्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने संकेत दिया कि मजबूत वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिये सरकार खर्च में कटौती करने के लिये कड़े कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की सफलता जारी रहेगी।

<><><><>

गेहूं खरीदी केन्द्रों पर व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा कल जिला और तहसील मुख्यालयों पर धरना दिया गया। भोपाल के पास मिसरोद आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि वास्तविक किसान अपना गेहूं बेचने के लिये मंडियों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं खरीदी केन्द्रों पर सक्रिय बिचौलिये उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। श्री भूरिया ने चेतावनी दी है कि प्रदेश सरकार ने यदि जल्दी ही इस पर अंकुश नहीं लगाया तो कांग्रेस जन–आंदोलन छेड़ेगी।

<><><><>

प्रदेश के 12 शहरों के मास्टर प्लान इस वर्ष तैयार किये जाएंगे, सके लिये नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में जिन शहरों के मास्टर प्लान तैयार होना है उनमें सागर, देवास, खंडवा, भोपाल, बांधवगढ़, पीथमपुर, दमोह, राघौगढ़, शुजालपुर, गोहद, गंजबासोदा और सिंगरौली शामिल है। भोपाल के मास्टर प्लान पर इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानिंग इंडिया की तकनीकी सिफारिश कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर एस. के कुलश्रेष्ठ के सामने विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नगर निगम द्वारा शहर के यातायात सर्वे का प्रेजेंटेशन आज किया जाएगा इसी आधार पर मास्टर प्लान में यातायात व्यवस्था का निर्धारण किया जाएगा। उधर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 258 शहरों के लिये सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जिनकी समीक्षा भी आज से शुरू की जाएगी।

<><><><>

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने आरोप लगाया है कि किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। कल इन्दौर में पार्टी की विशेष बैठक में हिस्सा लेने के बाद हमारे संवाददाता सुनील तिवारी से चर्चा करते हुए

उन्होंने कहा कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों के यहां छापे के दौरान करोड़ों की सम्पति मिल रही है, उस विभाग से जुड़े मंत्रियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई जरूरी है। सुश्री करात ने कहा कि बगैर मंत्रियों के प्रश्रय के अधिकारी भ्रष्ट तरीकों से सम्पत्ति अर्जित नहीं कर सकते । किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में गेहूं खरीदी में घोर अनियमितताएं हो रही हैं, जिसके लिये राज्य सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि गेहूं के बम्पर उत्पादन की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार को बारदानों का पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था। राष्ट्रपति पद के लिये संभावित उम्मीदवार के मुद्दे पर सुश्री करात ने कहा कि कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया है। भविष्य में जब भी कोई नाम सामने आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा।

<><><>

दक्षिण–पश्चिम मानसून इस वर्ष 20 जून तक मध्यप्रदेश में अपनी दस्तक दे सकता है। भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक डॉक्टर डी.पी. दुबे के अनुसार केन्द्रीय मौसम विभाग ने केरल तट पर मानसून एक जून तक आने की भविष्यवाणी की है। इसके चलते मध्यप्रदेश में ये 15 से 20 जून के बीच पहुंच सकता है।

<><><>

केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक को कल संसद ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा द्वारा इसे कल पारित किया गया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सीमा 3 वर्ष की बजाय 6 वर्ष करने का प्रावधान है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों के लाभ के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

<><><>

प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास और पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा देशी–विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के प्राकृतिक और नैसर्गिक दृश्यों के कारण फिल्म तथा सीरियल निर्माण में इजाफा हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन स्थलों को वायु सेवा से भी जोड़ा गया है तथा पचमढ़ी और खजुराहो जैसे सुंदर एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के लिये विशेष रियायती तैयार किये गये हैं।

<><><>

कल शाम मंदसौर जिले में महू–नीमच राजमार्ग पर बोतलगंज के एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा ट्रक और मोटर साइकिल के टकराने से हुआ, मृतकों में दो महिलाएं भी शामिल।